Nominations by the Government of Jammu and Kashmir

324. SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some nominations are made by Jammu and Kashmir Government for admission to Medical and Engineering Colleges in the country every year;

(b) if so, what is the number of seats for which nominations are made for admission in M.B.B.S., B.D.S. and Engineering courses and which are the colleges/States to which such nominations are made annually;

(c) the details of those nominations in 1989, 1990 and 1991;

(d) what is the criterion followed for such nominations; and

(e) whether the Government propose to nominate only state candidates who figure in the merit-list of the competitive examinations held for the purpose of selections next below the cut off merit line?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) to (e) The Ministry of Human Resource Development and the Ministry of Health and Family Welfare allocate certain seats to the Govt. of Jammu and Kashmir in the field of Engineering and Medicine respectively for making nominations to the institutions where the seats have been earmarked. The number of seats allocated in Engineering during 1989-90, 1990-91 and 1991-92 were 11, 15 and 15 respectively. The seats in medical subjects allocated during 1991-92 were 26 for M.B.B.S and 3 for B.D.S. respectivaly. No seats were allocated in medical subjects during 1989-90 and 1990-91.

खनिजों पर रायल्टी

325. **श्री लक्खीराम अग्रवाल :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार को कोयला तथा अन्य खनिजों पर देय रायल्टी की दरों में प्रत्येक तीन वर्षों के बाद संशोधन करना होता है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने रायल्टी की दरों में कब से संशोधन नहीं किया ;

(ग) सरकार द्वारा कोयला तथा अन्य खनिजों की रायल्टी की दरों में समय पर संशोधन न किये जाने के कारण कितना नुकसान हुआ है; और

(घ) क्या सरकार शीघ्र ही संशोधित दरों पर रायल्टी अदा करना आरम्भ करेगी और बकाया राशि भी जारी करेगी ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार, केन्द्र सरकार प्रधान खनिजों पर रायल्टी दरों को बढ़ा अथवा घटा सकती है; किन्तु केन्द्र सरकार रायल्टी दर में तीन वर्ष की अवधि में एक बार से अधिक वृद्धि नहीं कर सकती ।

(ख) कोयला तथा अन्य खनिजों की रायल्टी दरों में किए गए संशोधनों की तारीखें इस प्रकार हैं :—

खनिज का नाम	अंतिम संशोधन की तारीख	वह तारीख जिससे रायल्टी (दरों में वृद्धि देय थी)
कोयला	1-8-1991	13-2-1985
लिग्नाइट*	21-7-1990	—
अन्य खनिज	17-2-1992	5-5-1990

*लिग्नाइट को 21-7-1990 की अधिसूचना में पहली बार विशेष रूप से शामिल किया गया था ।